



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 05 जुलाई 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 277

महत्वपूर्ण एवं खास

एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीत, 164 विधायकों ने पक्ष में किया मतदान

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में जीत हासिल कर ली। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने विश्वास मत को बहुमत मिलने की घोषणा की। हाल में शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या घटकर 287 हो गई है, इसलिए बहुमत के लिए 144 मतों की आवश्यकता थी। शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के एक दिन बाद 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले में भूकंप के कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पांच किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली (आरएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में त्रिपुरा के बारदोवाली सीट से विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले श्री साहा ने यहां उच्च सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री साहा ने ट्वीट किया, आज, मैंने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को राज्यसभा के सदस्यता से अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। उन्होंने कहा, उन्हें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया।

जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने खुदकुशी, परिचालन बाधित

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर आज सुबह यात्रियों को पेशाना का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय संचिवालय से तक कुछ समय के लिए मेट्रो परिचालन प्रभावित रहा। दरअसल, जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर एक महिला यात्री मेट्रो के आगे कूद गई। चलती हुई मेट्रो के आगे कूदने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला को सफरदरज अस्पताल में ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। महिला कहां की रहने वाली है इसकी जानकारी भी नहीं मिल पायी है। उसकी पहचान की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

वायुसेना को 2023 से मिलने लगेंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए

पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस एमके-1 विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी होगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। टू फ्रंट वार की तैयारियों कर रही भारतीय वायुसेना को अगले साल से नई आसमानी लड़ाकू ताकत मिलेगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा और 2027 तक पूरे 83 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इनमें 73 तेजस एमके-1ए लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस एमके-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी। वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस एमके-1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। 11



अन्य ट्रेनर विमानों के पहले लॉट की आपूर्ति अगले साल मार्च तक होने की उम्मीद है। शेष चार विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक वायुसेना को की जानी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों का बढ़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है। इसीलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। वायु सेना चरणबद्ध तरीके से एलसीए वीरिएंट, एमआरएफए और एएमसीए के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के प्रयास में है। भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन

16 युद्धक विमानों और पायलट ट्रेनिंग के दो विमानों से मिलकर बनती है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन हैं जबकि टू फ्रंट वार की तैयारियों के लिहाज से कम से कम 38 स्क्वाड्रन होनी चाहिए इसलिए वायुसेना ने 2030 तक 8 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला लिया है। नई बनने वाली 8 स्क्वाड्रन का 75 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी एलसीए और पांचवीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयक्राफ्ट से पूरा किया जाना है। एलसीए एमके-1 के 40 विमानों का ऑर्डर पहले ही एचएएल को दिया जा चुका है। इनमें से 25 विमान मिल चुके हैं और वायुसेना की सेवा में हैं। इन 40 विमानों में एलसीए एमके-1ए के मुकाबले 43 तरह के सुधार किये जाने हैं। इनमें हवा से हवा में ईंधन भरने, लंबी दूरी की बिग्यांड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए दूर्यन के रडार और मिसाइलों को जाम करने के लिए

सिस्टम लगाया जाना है। एचएएल ने पिछले अनुबंध के अनुसार 32 जेट की असेंबली पूरी करने के बाद सिंगल-सीटर तेजस मार्केट जेट के निर्माण को रोककर 18 टू-सीटर ट्रेनर वीरिएंट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 8 ट्रेनर जेट पहले ऑर्डर से हैं और 10 एयरो इंडिया के दौरान किये गए 83 विमानों के दूसरे आदेश के हैं। वायु सेना को इनकी आपूर्ति मार्च, 2024 से शुरू की जाएगी और 2028-29 तक बेड़े में शामिल हो जायेंगे। तेजस एमके-1ए में डिजिटल रडार चेतवनी रिसीवर, एक बाहरी ईसीएम पॉड, एक आत्म-सुरक्षा जैमर, एईएसए रडार, रखरखाव में आसानी और एवियोनिक्स, वायुयुक्ति, रडार में सुधार किया गया है। तेजस एमके-1 में उन्नत शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल और एस्ट्रा एमके-1 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी। इन 123 तेजस एमके-1 और तेजस एमके-1ए की 6 स्क्वाड्रन बनाई जानी हैं।

कुल्लू में बस खाई में गिरी : 12 की मौत, कई घायल



शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नियोली-शानशेर मार्ग पर सैज घाटी के जंगला इलाके में एक निजी बस के चढ़ाने से गिरने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि एक स्कूल बस कुल्लू से सैज जा रही थी। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। रेस्क्यू अभियान जारी है। घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। माना जा रहा है कि स्कूल के बच्चे भी बस में थे। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक होंगे। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल व्यक्ति को तत्काल राहत के रूप में 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। घायलों का निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के ठिकाने से छह 'स्टिकी' बम समेत हथियारों का खजीरा बरामद

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के एक ठिकाने से चिपकने वाले (स्टिकी) छह बमों समेत हथियारों और गोला-बारूद का खजीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रियासी जिले के एक दूरस्थ गांव में लोगों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर तालिब हुसैन शाह और उसके साथी फैसल अहमद डार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद शाह ने इस ठिकाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाह ने पृष्ठताछ के दौरान राजौरी के द्राज गांव में आतंकवादियों का ठिकाना होने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद छापा मारा गया और ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। अधिकारी ने बताया कि ठिकाने से चिपकने वाले 6 बम, एक पिस्तौल, पिस्तौल की तीन मैगजीन, पिस्तौल के कारतूस, एक अंडर बैरल



ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), तीन यूबीजीएल ग्रेनेड, एक असांठ राइफल के 75 कारतूस और एंटीना के साथ एक आईईडी रिमोट बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने शाह और उसके कर्मियों साथी डार को चतुराई से निशाने कर दिया था, जिसके बाद दोनों को तुलकन टोक में गिरफ्तार किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों के साहस की प्रशंसा की और उनके लिए नकद इनाम की घोषणा की।

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीमकोर्ट सोमवार को सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की 'अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फ़िर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इस योजना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा कि भारतीय वायु सेना में जाने को इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल 20 साल से घटाकर चार साल कर दिया जाएगा।



वकील ने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण मामला है, कृपया इसे सूचीबद्ध करें। कई उम्मीदवारों के भविष्य दांव पर है। योजना को चुनौती देनी वाली याचिका दायर करने वाले वकील एम.एल. शर्मा ने कहा कि वह योजना से संबंधित सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि 70,000 से अधिक उम्मीदवार जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे वैश्विक महामारी से पहले से अपने नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब योजना के तहत उनका

कार्यकाल छोटा कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि जब आपने (शर्मा) दो साल से अधिक समय तक इंतजार किया है तो आप अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामला क्यों उठा रहे हैं। इसके बाद पीठ ने शर्मा की याचिका को अन्य मामलों के साथ उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। शर्मा ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने सशस्त्र बलों की बेहद पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार ने पिछले महीने, 'अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद

में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। याचिका में योजना के खिलाफ पूरे देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों का भी हवाला दिया गया। इससे पहले, शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर कर योजना के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन के दौरान रेलवे सहित सार्वजनिक संस्थानों को हुए नुकसान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में केंद्र और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को हिंसक विरोध-प्रदर्शनों पर एक स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

अमन अरोड़ा, डा. इंदरबीर निज्जर, फौजा सिंह सरारी, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और अनमोल गगन मान बने मंत्री

पंजाब कैबिनेट विस्तार

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब की भगवंत मान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री थे। आज पांच मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जिन्हें विधायकों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उनमें अमन अरोड़ा, फौजा सिंह सरारी, इंदरबीर सिंह निज्जर, अनमोल गगन मान और चेतन सिंह जौड़ामाजरा हैं।

सबसे पहले अमन अरोड़ा ने शपथ ली। अमन अरोड़ा, सुनाम से दूसरी बार विधायक बने हैं। अरोड़ा ने पिछला चुनाव



तीसरी शपथ फौजा सिंह सरारी ने ली। ये रिटायर्ड पंजाब पुलिस इंसपेक्टर सरारी बॉर्डर एरिया फिरोजपुर के मुफ्फरसहाय के विधायक हैं। सरारी, राय सिख बिरादरी से संबंधित हैं। राय सिख बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक फिरोजपुर एरिया में है।

चौथी शपथ चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने ली। चेतन सिंह जौड़ामाजरा चुनावी जीत के बाद खूब मशहूर हुए। 7 साल साउथ कोरिया में दिहाड़ी की वापस लौटते तो एक बार जान पर खेलकर लडकी को किडनेप होने से बचाया था। हालांकि, सबसे अहम सरकार पंढियाला जिले को प्रतिनिधित्व देना है। चेतन समान से विधायक हैं।

पांचवी शपथ अनमोल गगन मान ने ली। अनमोल खरड़ से विधायक हैं। उन्होंने पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) उम्मीदवार रंजीत सिंह गिल को 37,718 वोटों के अंतर से हराया था। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार बनाने के तीन महीने से ज्यादा समय बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद आज पांच और विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 18 है।

एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन में 21.7 % से अधिक की बढ़ोतरी हासिल की

नई दिल्ली (आरएनएस)। एनटीपीसी समूह की कंपनियों ने अप्रैल से जून 2022 तक पहली तिमाही में 104.4 बीयू का उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में सूचित 85.8 बीयू की तुलना में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जून 2022 के महीने में, उत्पादन 34.8 बीयू था, जो जून 2021 में 26.9 बीयू की तुलना में 29.3 प्रतिशत अधिक है। यह बेहतर प्रदर्शन और चालू वर्ष में बिजली की मांग में वृद्धि का संकेत देता है। उड़ीसा में एनटीपीसी तालचर कनिहा (3000 मेगावाट) अप्रैल से जून 2022 के बीच 94.2 प्रतिशत

प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला थर्मल पावर प्लांट रहा है। एनटीपीसी कोयला स्टेशनों का कुल प्लांट लोड फैक्टर अप्रैल से जून 2022 तक 80 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 69 प्रतिशत की तुलना में, बिजली संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में उच्च स्तर की परिचालन उत्कृष्टता और एनटीपीसी की विशेषज्ञता का प्रमाण है।

एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन, अपशिष्ट से ऊर्जा और ई-गतिशीलता जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक भी 2032 तक

शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य बना रहा है। एनटीपीसी ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीई) के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है।

बिजली उत्पादन के अलावा, एनटीपीसी द्वारा हाइड्रो, पवन और सौर जैसे स्वच्छ और हरित स्रोतों और हरित हाइड्रोजन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में विविधता लाई गई है। प्रमुख विद्युत कंपनी ने ईंधन सेल, ई-मोबिलिटी और वेस्ट-टू-एनर्जी सहित कई तरह के व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कदम रखा है।

कोई भी होटल या रेस्तरां खाद्य बिल में स्वतः या गलती से सेवा शुल्क नहीं लगा सकता: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली (आरएनएस)।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीसी) ने होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या गलती से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिखा जा सकता। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क



का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट तौर पर बताया कि सेवा शुल्क ऑप्टिकल, वैकल्पिक और उपभोक्ता का अधिकार है। सेवा शुल्क के

संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर

एकत्र नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों को लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता को यह पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। साथ ही, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, जो मुकदमा पूर्व-स्तर पर

वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के रूप में काम करती है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए ई-दखिल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता जांच और सीसीपीए द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए सम्बद्ध जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीपीए को शिकायत ई-मेल पर भेजा सकता है।